











# संपादक की कलम से

## **भाजपा के दक्षिण भारत में बनत- बिगड़ते रिश्ते क्या कहते हैं ?**

हाल ही में भाजपा का कर्नाटक में जनता दल संक्षयुलर (जेडीएस) से गढ़बंधन हुआ और तमिलनाडु में एआईएडीएमके से नाता टूट गया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि इस पर किसी को सोचन झाँ संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल सत्ता के गलियारे में तैर रहा है कि वया तमिलनाडु में एआईएडीएमके से संबंध टूटने से केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को कोई खास फर्क पड़ेगा इस सवाल की वजह ये है कि 2019 में जब औपचारिक गढ़बंधन हुआ उससे पहले से एआईएडीएमके का भाजपा के प्रति सहयोगात्मक रूपैया जगजाहिर रहा है। खासकर राज्यसभा में, जहां कुछ दिन पहले तक भाजपा का बहुमत नहीं था और बहुत जरूरी विधेयकों का पास करने में उसे सहयोग की जरूरत थी। लेकिन तमिलनाडु में गढ़बंधन की खट्टी इमें डालने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने किया। वो न केवल एआईएडीएमके के नेतृत्व के आलोचक थे बल्कि उन्होंने सीएन अन्नादुरै के आइकन को निशाना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा।

अन्नादुरै को द्विविध पार्टियों का जनक माना जाता है। एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के मन में दोनों के प्रति सम्मान है और व्यावहारिक रूप से वे दोनों को पूजते हैं। राजनीतिक गलियारे में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि बिना ताकतवर केंद्रीय नेतृत्व के इशारे के, क्या गढ़बंधन में जूनियर पार्टनर का नेता, तमिलनाडु जैसे राज्य में ऐसे आइकन का मजाक उड़ाने की हिम्मत जूता सकता है दिलचस्प बात ये है कि एनडीए गढ़बंधन से अलग होने की घोषणा, बेजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एआईएडीएमके नेताओं की मीटिंग के बाद की गई। वैसे कुछ राजनीतिक विशेषक बताते हैं कि ये गढ़बंधन टूटा नहीं है। ये एक रणनीतिक चाल है। ये उसी तरह है जैसे असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में जाते हैं और मुस्लिम वोट विभाजित होता है। ये ऐसा नहीं है जैसे उद्धव ठाकरे अलग हुए हों। वे नड्डा से मिलने दिल्ली गए थे। पृथक्षूमि बिल्कुल रस्पष्ट है। अन्नामलाई तो सिर्फ बहाना है। लेकिन कर्नाटक में भाजपा जेडीएस के साथ गढ़बंधन करके अपनी 1998 और 1999 की रणनीति को ही दुरहा रही है। जेडीएस के मुखिया पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा हैं और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 125 साल पहले भाजपा ने रामकृष्ण हैंगड़ी की लोक शक्ति पार्टी के साथ गढ़बंधन किया था और कर्नाटक से लोकसभा में असरदार एंट्री की। सबसे अहम बात है कि कर्नाटक के चुनावी इतिहास में इन दो चुनावों को, एक जन नेता वाली स्थानीय पार्टी के बोटों का एक राष्ट्रीय पार्टी को चले जाना का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है।

इन दो चुनावों में हैंगड़े ने अपने लिंगायत वोट आधार को भाजपा के हवाले कर दिया। ये दोनों दफे हुआ, जब वो लोक शक्ति पार्टी के नेता रहे और फिर जनता दल (यु) के नेता बने कर्नाटक के दक्षिणी ज़िलों, जैसे कोलार, टुमाकुरु, चिककाबालापुर, मांड्या, बैंगलुरु कुरुक्षेत्र, चम्पग्ननगर और हासन में भाजपा भासि पार्टी को टूटगांव जावटी है।

रल, यामराजनगंगा और छासन में भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन का तुराना पाहता है। इन इलाकों में वोकालिगा बहुसंख्यक हैं और ये जेडीएस का आधार क्षेत्र है। वैसे उस गठबंधन का असर 2004 के विधानसभा चुनावों के परिणाम में दिखा। इस बार भाजपा ने तय किया है कि वो 24 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगी, यानी 2019 में जितनी सीटें जीती थीं उससे एक कम। ये बताता है कि 2023 के हालात 2019 से अलग हैं। तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई और एआईएडीएमके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी के बीच खींचतान की बड़ी वजह उनकी राजनीतिक प्रतिदिव्यता बताई जाती है क्योंकि दोनों ही पश्चिमी तमिलनाडु में दबदवा रखने वाले गौंडर समुदाय से आते हैं। राजनीतिक विश्वेषक तो यह भी कहते हैं कि अन्नामलाई केंद्रीय नेतृत्व के च्होरे इसलिए बने हुए हैं क्योंकि राज्य में उन्होंने भाजपा को चार्चा में ला दिया है। अगर दो पार्टियां आपस में वोट बांटती हैं तो डीएमके को फायदा होगा। फिलहाल ये होता नहीं दिख रहा है। भाजपा के लिए तो यही बहुत है कि उसका वोटिंग प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन एआईएडीएमके और पलानीस्वामी के लिए तो सीटें जीतना जरूरी हैं, वरना उनके नेतृत्व को खतरा पैदा हो जाएगा। जानकर लोग इस नजरिए से सहमत हैं कि चुनाव के बाद, केंद्र में भाजपा को एआईएडीएमके की ओर से हमेशा की तरह समर्थन मिल सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड़ी से उलट, पलानीस्वामी बिल्कुल अलग हैं। रेड़ी आंध्र प्रदेश में मुख्य खिलाड़ी हैं। लेकिन पलानीस्वामी के साथ तमिलनाडु में ऐसा नहीं है एआईएडीएमके को अपनी वोट हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गठबंधन की जरूरत है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में पलानीस्वामी ने एआईएडीएमके नेता गठबंधन की अच्छी तरह से अनुगाई की थी। गठबंधन ने जो 75 सीटें हासिल की थीं उनमें एआईएडीएमके के हिस्से 66 सीटें आई थीं बताया जाता है कि उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में हार की भरपाई की, जब डीएमके ने राज्य की 39 लोकसभा सीटों में 38 सीटें हासिल की थीं। तबस न तो कोई नेता और न ही कार्यकर्ता पार्टी छोड़ कर गया। असल में, जब गठबंधन टूटने की घोषणा हुई तो एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई कार्यकर्ताओं का मानना है कि अन्नामलाई एआईएडीएमके की कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं।

अलग रहा है।

A black and white portrait of a man with a mustache and short hair, wearing a light-colored button-down shirt. He is looking slightly to his right with a neutral expression. The background is out of focus, showing what appears to be an indoor setting with some furniture.



है। लालू खानदान को भले ही जमानत पर जमानत मिलतीं जा रही है किन्तु नीतीश बेहतर समझते हैं कि लोकसभा चुनाव तक लालू खानदान से भी ईड़ी की धरपकड़ होते ही बिहार में आपसी टकराव बढ़ने के साथ साथ सीटों की लड़ाई भी चरम पर पहुंच जाएगी।

परिणाम आरजेडी और जेआरडी में भी तलवारें खींचना भी तय है। संभवतः दोनों दलों से कई विधायक ओर सांसद भी पीछे के दरवाजों से भाजपा का हाथ थाम सकते हैं। जाति राजनीति से गमार्ती अवाम ओर अपनों का दर्द बिहार को सीएम नीतीश ने जातिगत समीकरण के रंग में रंग कर पूरे देश में एक तर्जा बनाया जाना कर दिया है। भाजपा दिग्गजों की आपसी लड़ाई से बिहार आम जनता राहत गांधी को गुमराह करने वाले ओर कोठे नहीं है, उनके आगे वीर पार्टी के तेजा और

# ईरानी जेल में रहते नोबेल जीती मानवाधिकार योद्धा नरगिस.ईरानी



चढ़ाने की घोषणाएं सुनने के लिए उनका घड़ी देखना। नरगिस तब न्यूक्लियर फिजिक्स का पढ़ाई कर रही थी। काजिवन शहर में उसके भावी साथी ताधी रहमानी से मुलाकात हुई। वे भी खुद राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं। इरान में उन्हें भी 14 साल की जेल हुई थी। वह फ्रांस में अपने दो बच्चों के साथ निवास जीवन जी रहे हैं।

नरगिस अपनी साहस्री युवतियों की क्षमा करती है। इन जुझारू लड़कियों और महिलाओं ने स्वतंत्रा और समानता के लिए अपनी बहादुरी से पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया। नरगिस हमेसा कहती हैं : हँजीत आसान नहीं है, लेकिन यह निश्चित तो है। अपनी किशोरावस्था में नरगिस इरानी

वह महिलाओं को इतने हजार प्री देने की घोषणा कर रहे हैं तो यह इतने हजार प्री देने की घोषणा कर रही है, ऐसे में जनता जनराजन को चुनावी पर्व में आनंद आना स्वाभाविक बात भी है। इसके अतिरिक्त चुनाव से एक दिन पहले भी रात को प्रसिद्ध पुरानी कहावत कल्प की रात आई यह भी बालते हैं, क्योंकि उस रात जनता पर हरों की बारिश भी होती है। यह मैंने स्वयं ने भी अपने पड़ोस में अपनी आंखों से देखा है किस तरह कार्यकर्ता थैली में लेकर आते हैं और जितने घर के मेंबर उतने हरे देकर जाते हैं! ? खैर यह तो अंदर की बात है, परंतु यह मुफ्त की घोषणाएं वर्तमान में ही नहीं इसकी प्रथा 1954 से देखने को मिल रही है, जिसकी चर्चा हम नीचे पैरा में करेंगे त्वार्किं अभी दो राज्यों में चुनाव आयोग ने सर्वे कर लिया है, तारीखें घोषित करने के लिए उच्च स्तरीय सभा हो गई है उम्मीद है बहुत जल्द तारीखें घोषित हो जाएगी इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत में 70 वर्षों से जारी चुनावी प्री स्कीम्स को बंद करने का स्थाई समाधान ढूँढ़ना समय

उलाओं के अधिकारों, मृत्युदंड के खासे र राजनीतिक कैदियों को कढ़ी सजाओं के लाफ अखबारों में लिखती रहीं। पति के रान स्थित कार्यशाल से ही वह लाइव डेयो प्रसारण करती थीं। इंजीनियर थीं। वह दशकों से इरान में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स को फंडस में शामिल थीं, जो मृत्युदंड को घट करने के लिए ईरानी वकील शिरीन दी द्वारा स्थापित किया गया था। इबदी को 03 में नोबेल शार्ट पुरस्कार से नवाजा था। नरगिस को पहली बार 2011 में प्रपत्रार किया गया। हृद न्यूयॉर्क टाइम्स ह की एक मुताबिकः हॉन्यायपालिका नरगिस को बार सजा दे चुकी है। इस साल उनके लाफ तीन और न्यायिक मामले खोले गए

# मुफ्त की च

मांग है।  
थियों बात अगर हम सीईओ के विचारों  
र पांच राज्यों में चुनाव तारीखों की करें  
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ने  
वार को कहा था कि निर्वाचन आयोग  
तंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रलोभन मुक्त  
चाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।  
चाव में धनबल, मुफ्त की रेविडियों आयोग  
रडार पर होंगी। देश के पांच राज्यों में  
लाल महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।  
चाव की तारीख का एलान अभी नहीं हुआ  
लेकिन कहा जा रहा है कि इसको लेकर  
इम जानकारी सामने आई है। कहा जा  
है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते और दिसंबर  
पहले हफ्ते के बीच पांच राज्यों में चुनाव  
ए जा सकते हैं। जिन राज्यों में  
विधानसभा चुनाव होने हैं, वो राज्य हैं-  
संस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना  
र मिजोरम विधानसभा चुनाव की तारीखों  
लेकर दिल्ली में पर्यवेक्षकों की अहम  
क हो गई है। इस बैठक में मुख्य चुनाव  
युक्त के अलावा दोनों चुनाव आयुक्त भी  
मिल थे। साथ ही जनरल ॲब्जर्वर,  
सर्पेंडिचर और सिक्योरिटी ॲब्जर्वर भी

अतिरिक्त सजा का कारण बन सकते हैं। नरगिस जेल में भी दूसरे कैदियों के साथ दर्दनार्थी अयोजित करती रहीं। उनकी किताब द्वाइट टार्चर्ल 2002 उस समय प्रकाशित हुई जब दिल की सर्जरी के बाद कुछ दिनों बाद लिए घर पर थीं। नरगिस की व्यथाकथा ढकर, सुनकर यकीन हो जाता है कि इस्लामी ईरान आज भी सोलहवीं सदी में जी रहा है। तब सफाविद बादशाह तहमास्प ने गल भगोड़े मिर्जा मुहम्मद नसरीरुद्दीन हमायून गोते तेहरान में पनाह दी थी। सप्ताह शेरशाह रुरी से चौसा और कन्नौज में हारकर हुमायून रान आया था। शिया बन गया था। फिर लल्ली का राज पा लिया। ईरान में इन चर्च सदियों में स्त्री जीवन में कोई प्रगतिवादी बदलाव नहीं आया। शरीयत कानून के तले हिलाएं जीती रहीं। नरगिस को यही आकायत रही। उसके संघर्ष का यही आधार था। नरगिस जब कोड़ों की मार सह रही थी तभी उसी समय इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में कोड़ों की सजा पर रोक लगा दी गई। कोड़े मारने की सजा को जेल या जुमार्ने बदला गया है। इस निर्देश को शाह सलमान और उनके बेटे गजन धिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर मानवाधिकार सुधारों को विस्तार देने के लिए उठाया गया था।

तेहरान की नारकीय कारागार (जेडिन-एविन), जहां नरगिस कैद हैं, का भी तेहास है। भारत के पांच केंद्रीय जेलों में रह माह (1976-77) बिताने के कारण एविन विविध कैदखानों से दिलचस्पी स्वाभाविक है। तेहरान में इस इविन जेल में कई श्रमजीवी पत्रकारों ने दम तोड़ा। पहलवी बादशाह रजा शाह के दैरान गुत्तचर संस्था सावाक के कई शिकार हुए। मगर खुमैनी शासन में तो अखबारनवीसों को बेरहमी से मारा गया। नरगिस तो जीवित शहीद हैं। इस जेल में 15,000 कैदी हैं। सौ के करीब लोगों को तन्हा कोठरी में बंद किया गया है। ज्यादातर लोग मीडियाकर्मी और जनांदोलनकारी हैं। मसलन एक स्कूल अध्यापिका थी मरीना नेमत उसे यातना देकर मुल्लों ने मार डाला। कनाडा की फोटो-पत्रकार थी जाहरा काजमी जिसने जेल में यातना की चित्र खींची थी। उसे तड़पा कर मारा। संगीतकार हांगी ताबकीरी को तन्हा कोठरी में मानसिक पीड़ा दी। मर गयी। अमेरिका से ईशा मोटेनी ईरान में नारी अधिकार की अध्ययन करने आई थीं। उसे (11 नवंबर 2008) को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कैद रखा। अमेरिकी-ईरानी पत्रकार रुक्साना सबेरी को जासूसी में पकड़ा। कनाडियन पत्रकार माजीर बहारी को ईरान-विरोधी किताब लिखने पर सजा दी। ईरान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (3 अगस्त 2009) महमूद अहमद निजाद ने तो कहा था : हृजेल में बलाकार हुए हैं पर शरु ही उसका दोषी है हृउ उस वक्त विपक्ष के प्रत्याशी महंदी करौबी ने आरोप लगाया था कि हृजांचकर्ता पुलिसवाले बलात्कार को तहकीकात का सरल तरीका बनाते हैं हृतो ऐसी जेल व्यवस्था में नरगिस की आंखों के नूर की हिफाजत केवल खुदा ही कर सकता है। इन हैवानों से।

# घोषणाओं की बारिश

जूद थे। अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों  
एतान हो सकता है। मीडिया में एक  
पोर्ट केमुतबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश,  
जोरम और तेलंगाना में एक चरण में  
चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार भी इन  
ज्यों में एक ही चरण में मतदान हुआ था।  
हीं, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव कराए  
गए की संभावना है। मिजोरम विधानसभा  
कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को  
पत्त हो रहा है। वहीं, तेलंगाना, राजस्थान,  
तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं  
कार्यकाल अगले साल जनवरी में खत्म  
गा।

थियों बात अगर हम दो गाजों में मुफ्त  
घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल  
खिल करने और नोटिस जारी होने की करें  
गा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के  
ख्यमत्रियों की तरफ से चुनाव से पहले की  
रही घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट  
याचिका दायर की गई है इस मामले में  
प्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यसरकारों केंद्र और  
चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है।  
पत की घोषणाओं पर पहले से लंबित  
याचिका के साथ इस मामले को भी जोड़ा

गया है। याचिकाकर्ता का कहना था कि  
चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही  
योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही  
बोझ पड़ता है राजस्थान और मध्य प्रदेश में  
विधानसभा चुनाव से पहले लोगों के लिए  
ऐसी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है,  
जिसमें उन्हें कैश दिया जाएगा। इसे प्रीबीज  
भी कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके  
खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।  
चीफ जस्टिस ने कहा कि चुनाव से पहले  
सभी तरह के बादे किए जाते हैं। इसपर  
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यहां  
सिर्फ बादों की बात नहीं हो रही है, इसकी  
बजह से नेट वर्थ निगेटिव हो रहा है। नेता  
जिला जेल को बेचने तक की हद तक चले  
गए हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली  
बेंच ने यह भी कहा कि इस मामले को भी  
मुफ्त के बादों पर पहले से लंबित याचिका  
के साथ सुना जाएगा। राजनीतिक दलों की  
ओर से चुनाव जीतने के लिए की जाने वाली  
मुफ्त की घोषणाओं के खिलाफ वकील  
अश्वनीउपाध्याय की याचिका पहले से  
लंबित है।

नई याचिका मध्य प्रदेश के रहने वाले ने

# चुनावी शंखनाद में जातिगत राजनीति ओर संजय की गिरफ्तारी के मायने

डाक्टर तेजसिंह किराड  
(वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्वेषक,  
नागपुर से)

इसे आप पार्टी का दर्भाग्य कहे या



# विदेश संदेश

## कनाडा में विमान हादसा, पायलट समेत तीन की मौत

ब्रिटिश कोलंबिया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। हादसा चिल्कैक शहर में हुआ। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो इंजन बाला यह विमान



(पाइप पीए-34) सेनेका स्थानीय हवाई अड्डे के पास एक मोटर के पीछे पेंडों और झाँड़ियों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चिल्कैक शहर वैकूवर से लगभग 100 किलोमीटर (62 मील) पर्वत में है। कनाडा के अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच चल रही है। हादसे में पायलट सहित विमान पर सवार सभी तीन लोग मारे गए। गोल कैमेरेड यात्री ने कहा कि वह परियों को सूचित कर रही है।

## पाकिस्तान के सबसे बड़े एटमी प्लांट के पास जबरदस्त धमाका, ड्रेन हमले की आशंका

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के पास धमाका हुआ है। यह परमाणु प्लांट पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में हमले कर रहा पिछले कई सालों से तहरीक-ए-तालिबान के निशाने पर है। हालांकि, इस हमले की अपील तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन तालिबान ने पहले इस परमाणु इकाई पर हमले की कई धमाकियां दी हैं। इस धमाके के पीछे ड्रेन हमले की आशंका जारी रही है। डीजी खान में पाकिस्तानी सेना की न्यूक्रियलर फैसिलिटी में हुए धमाके के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार बड़ी संख्या में सरकार और अनिश्चयन वाहन न्यूक्रियलर फैसिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। विस्फोट स्थल से 50 किमी दूर तक लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। पाकिस्तानी सेना के परमाणु संयंत्र के पास हुई धमाका हुआ है। उसके बाद दोपहर 12 बजकर 12 मिनट पर 5.5 तीव्रता का धूकंप आया। उसके बाद दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 6.3 तीव्रता का धूकंप आया। उसके बाद दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर 5.5 तीव्रता का धूकंप आया। इसके बाद 12 बजकर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटमी पर हमले की कई धमाकियां दी हैं। इस धमाके के पीछे ड्रेन हमले की आशंका जारी रही है। डीजी खान में पाकिस्तानी सेना की न्यूक्रियलर फैसिलिटी में हुए धमाके के बाद स्थानीय लोगों के अनुसार बड़ी संख्या में सरकार और अनिश्चयन वाहन न्यूक्रियलर फैसिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। विस्फोट स्थल से 50 किमी दूर तक लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। पाकिस्तानी सेना के परमाणु संयंत्र के पास हुई धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों को संचारित विकिरण से बचाने के लिए जल से जल्द थोड़े डोरे के लिए कहा गया है।

पीड़िया रिपोर्ट्स के मुताबिक एटमी पर हमले की कई धमाकियां दी हैं। धमाका होने की जगह के कीरीब ही यूरोपियन का प्लांट भी लगा हुआ है। फिलावल इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धमाके की जगह के कीरीब ही यूरोपियन का प्लांट भी लगा हुआ है। फिलावल इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने धमाके की जगह के कीरीब ही यूरोपियन का प्लांट भी लगा हुआ है। जिसमें द्विध रहा है कि डेरा गाजी खान की ओर सुरक्षा बलों की गाड़ियां स्पृष्ट पर रही हैं, इनके साथ कई दिन बालू भी दिखाई दिए हैं। वायरल भागी जारी हैं, जिनके साथ कई दिन बालू भी दिखाई दिए हैं। लेकिन अपील तक पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान समान नहीं आया है और ना ही संबंधित विभाग ने कोई प्रतिक्रिया दी है।

## पाकिस्तान का दोगलापन, सीएए पर भारत का विरोध करने वाला खुद दिखा रहा अवैध प्रवासियों को बाहर का रास्ता

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने कीरीब 17 लाख अफगान शरणार्थियों समेत सभी अवैध प्रवासियों को 31 अक्टूबर तक देश से बाहर निकालने की अपीली योजना पर आगे बढ़ा कर फैसला किया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों को देखते हुए लिया गया है। बता दें, यह कम्पन ऐसे समय में उठाया गया है, जब कानून प्रवर्तन ऐंजेसियों उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, जिन्हें वे अवैध प्रलिंग कहते हैं। गैरतलब हैं, पिछले एक हफ्ते में बड़ी संख्या में परिवार सीमा पार करके अफगानिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं।

कार्बनावक विदेश मंत्री जिलानी ने कहा कि कोई भी देश अपने यह अवैध संघर्ष से आए लोगों को नहीं रहने देना चाहता है। चाहें वो यूरोप हो या दुनिया में कोई और देश। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास को देखते हुए यह फैसला लिया है।

गैरतलब है, अवैध प्रवासियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए जिलान के निकालने का सामना करने के लिए कहने के पाइकिस्तान के फैसलों को आलोचना हो रही है। यूरोपियन चूनार तथा एमेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने सरकार से अपनी योजनाओं पर पुनर्निवार करने की मांग की है। काबुल में तालिबान सरकार ने भी इस कदम पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है।